



सत्यमेव जयते

बमारी
कमलपुत्र विवाह एक

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PD. 250
KM. 30
CPB-220

k

सं. 210]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2004/वैशाख 21, 1926

No. 210]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2004/VAISAKHA 21, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 22 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 304(अ).—वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435 एक्स तथा धारा 456 एवं नौटिकल स्कन्ध परिपत्र-सेफमैन/1/2004 सं. 10-एनटी(6)/2001-1 दिनांक 01 जनवरी, 2004 में आंशिक आशोधन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गहरे समुद्र में मत्स्य जलयानों पर यथा प्रयोजनीय रूप से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 76 तथा इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत जनसंयोजन अपेक्षाओं के 50% की सीमा तक ही विदेशी नागरिक होंगे, इस प्रकार के जलयान भले ही समुद्र में हों या पत्तन पर, यह अधिसूचना 15 मई, 2004 से निश्चित रूप से प्रभावी हो जाएगी।

नौवहन महानिदेशक ने यह निर्णय भी लिया है कि किसी भी परिस्थिति के अन्तर्गत समय सीमा को और नहीं बढ़ाया जाएगा।

[फा. सं. सीएस-12(1)/2004]

द्वारा आदेशित,

पी. एच. कृष्णन, उप नौवहन महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING

(DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd April, 2004

G.S.R. 304(E).—In exercise of powers conferred on the Central Government under Section 435 X and Section 456 of the Merchant Shipping Act, 1958 and in partial modification of Nautical Wing Circular-Safeman/1/2004 No. 10-NT(6)/2001-1 dated 1st January, 2004, the Director General of Shipping and ex-officio Additional Secretary to the Government of India, is pleased to decide that the stipulation of foreign nationals to the maximum extent of 50% of manning requirements under the provisions of Section 76 of the Merchant Shipping Act, 1958 and notifications made thereunder, as applicable, to the Deep Sea fishing vessels, shall positively come into force from 15th May, 2004, irrespective of whether such vessels are at sea or in port.

It has also been decided by the Director General of Shipping that no further extension will be considered under any circumstances.

[F. No. CS-12(1)/2004]

By Order,

P.H. KRISHNAN, Dy. Director General of Shipping